“ भारतीय रेलवे राष्ट्र की विकास यात्रा का इंजन है ”

नरेंद्र मोदी
प्रधानमंत्री

सत्यमेव जयते
भारत सरकार

सत्यमेव जयते
भारत सरकार

न्यू इंडिया का इंजन

5 वर्ष
रेल एवं कोयला मंत्रालय की
उपलब्धियां व पहल

भारत सरकार, 2019

सुरक्षा

2018-19 में अब तक का
सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा रिकॉर्ड

भारतीय अर्थव्यवस्था का वाहक

डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के
2 खंड पूर्ण

इनोवेट इन इंडिया

डीजल लोकोमोटिव वर्क्स,
वाराणसी में विश्व में पहली बार,
डीजल लोको का बिजली के
लोको में परिवर्तन

सबसे लम्बा रेल-सह-सड़क पुल

बोगीबील पुल
अरुणाचल प्रदेश को
शेष भारत से जोड़ेगा

नामुमकिन अब मुमकिन है

1.5 लाख भर्तियों का अब तक का सबसे बड़ा अभियान लगभग पूर्ण

अगले 2 वर्षों में अतिरिक्त 2.3 लाख भर्तियां

मेक इन इंडिया

पहली स्वदेशी
सेमी हाई स्पीड
ट्रेन-वंदे भारत एक्सप्रेस

सुरक्षित क्रॉसिंग्स

ब्रॉडगेज नेटवर्क पर
सभी मानवरहित
रेल फाटक समाप्त

रेल विद्युतीकरण

शत प्रतिशत ब्रॉडगेज
रूटों का विद्युतीकरण
स्वीकृत

सुरक्षा सर्वप्रथम

152
2013-14

29
2018-19*

मृतकों की संख्या

2018-19 में अब तक का सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा रिकॉर्ड

मृतकों की संख्या में 81% की कमी

*(जनवरी 31, 2019 तक)

ब्रॉडगेज नेटवर्क पर सभी मानवरहित रेल फाटक समाप्त

1,137 मानवरहित रेल फाटक प्रतिवर्ष 2009-14

3,479 मानवरहित रेल फाटक 2018-19

तेज़ गति से रेल नवीनीकरण

2,926 किमी. 2013-14

5,000 किमी. 2018-19 में अपेक्षित

50 साल पुराने डिज़ाइन वाले आई सी एफ कोचों का उत्पादन बंद

सुरक्षा सर्वोपरि

₹1 लाख करोड़ के राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष (आर.आर.एस.के.) का सृजन

फुट ओवर ब्रिजों व हाई लेवेल प्लेटफार्मों पर विशेष ध्यान

23 प्रतिवर्ष 2009-14

74 प्रतिवर्ष 2014-18

प्रतिवर्ष 3 गुना अधिक फुट ओवर ब्रिजों का निर्माण

2017-18 में अब तक के सर्वाधिक रोड ओवर ब्रिज/ रोड अंडर ब्रिज/ सबवे का निर्माण

415 प्रतिवर्ष 2004-14

1,220 प्रतिवर्ष 2014-18

प्रतिवर्ष औसत निर्माण में 3 गुनी वृद्धि

सुरक्षा

सभी ट्रेनों में व स्टेशनों पर सी सी टी वी निगरानी प्रणाली की स्थापना की जा रही है

2014 से अब तक 45,200 बच्चे बचाए गए

महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के लिए 547 व्यक्तियों को राजकीय रेलवे पुलिस (जी आर पी) को सौंपा गया

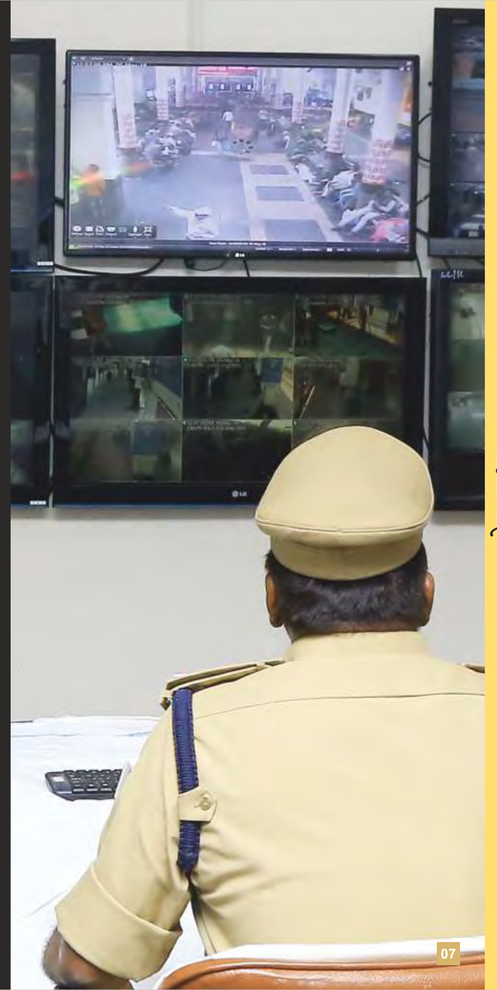

पूंजीगत व्यय में अभूतपूर्व वृद्धि

2014-19 में कुल पूंजीगत व्यय 2009-14 की अपेक्षा दो गुने से अधिक

2019-20 हेतु पूंजीगत व्यय ₹1.58 लाख करोड़ (अब तक का सर्वाधिक)

₹2.3 लाख करोड़ (2009-14)

₹5.1* लाख करोड़ (2014-19)

*संशोधित अनुमान 2018-19 सहित

क्षमता वृद्धि को बल

रेल लाइनों की कमीशनिंग में तेज़ी

नयी लाइन/दोहरीकरण/तीसरी व चौथी लाइन परियोजनाओं की औसत कमीशनिंग दर 59% अधिक

4.1 किमी. प्रति दिन 2009-14

6.53 किमी. प्रति दिन 2014-18

2019-20 में 15.34 किमी. प्रति दिन का लक्ष्य

बोगीबील पुल:
विकास की कमी होगी पूरी

भारत का सबसे लम्बा
रेल-सह-सड़क पुल
4.94 किमी. लम्बा

स्टेट-ऑफ़-द-आर्ट
तकनीक व मशीनों
का प्रयोग

1997-98 में स्वीकृत,
फ़ास्ट ट्रैक पर
अब पूर्ण किया गया

ईटानगर से डिब्रूगढ़ की यात्रा दूरी मात्र 180 किमी.

दूरी में 700 किमी.
से अधिक की कमी

यात्रा समय 24 घंटे से
घटकर केवल 5 घंटे

भारत को जोड़ती - ज़िंदगियों को जोड़ती

पूर्वोत्तर में कनेक्टिविटी को बढ़ावा

- निर्बाध कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए पूर्वोत्तर में सम्पूर्ण नेटवर्क ब्रॉड गेज में परिवर्तित
- पूर्वोत्तर के सभी 7 राज्य (असम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर एवं अरुणाचल प्रदेश) रेल नेटवर्क से जुड़े
- 2014 में केवल गुवाहाटी ब्रॉड गेज से जुड़ा था
  - अब ईटानगर एवं अगरतला भी जुड़े
  - 2020-21 तक शेष राजधानियां भी जुड़ जाएँगी
- जिरिबाम-तुपुल-इम्फाल नई रेल लाइन परियोजना के अंतर्गत भारत का सबसे ऊँचा पुल निर्माणाधीन

उपनगरीय नेटवर्क पर विशेष जोर

बेंगलुरू उपनगरीय नेटवर्क का विकास: ₹15,700 करोड़ से अधिक लागत की परियोजनाएं प्रगति पर

- 15 लाख से अधिक दैनिक यात्री लाभान्वित
- वातानुकूलित कोचों वाली आधुनिक प्रणाली, स्टेट ऑफ़ द आर्ट सिग्नलिंग और आधुनिक स्टेशन

मुंबई उपनगरीय नेटवर्क का विकास: ₹70,000 करोड़ से अधिक लागत की परियोजनाएं प्रगति पर

- 75 लाख से अधिक दैनिक यात्री लाभान्वित होंगे
- 2014 से अब तक 214 नयी सेवाएं जोड़ी गईं
- वातानुकूलित कोचों से यात्रियों को अधिक आराम
- लंबित नेरुल-सीवुड/बेलापुर-उरन नई लाइन परियोजना नवम्बर 2018 से प्रारम्भ
- **विजुअल अलार्म इंडिकेशन सिस्टम (वी ए आई एस) :** यात्री सुरक्षा के लिए कोच द्वार पर गाड़ी के आरंभ का संकेत देता नीला प्रकाश सिग्नल

न्यू इंडिया को रफ़्तार देती
वन्दे भारत एक्सप्रेस

दिल्ली और वाराणसी के मध्य पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन

- ट्रेन 18 रेक का प्रयोग
  - मेक इन इंडिया उत्पाद: भारत की पहली हाई-टेक, ऊर्जा-दक्ष, सेल्फ-प्रोपेल्ड ट्रेन
  - भारत में बढ़ते उपयोग के साथ वैश्विक निर्यात भी
  - 160 किमी./घंटा की अधिकतम गति
- दिल्ली एवं वाराणसी के बीच चलने वाली सबसे तेज़ ट्रेन से भी 35-40% तेज़
- गति बढ़ाने और घटाने की बेहतर क्षमता के कारण यात्रा के समय में काफी कमी
- यात्री आराम हेतु विश्व स्तरीय सुविधाएँ
- 130 ट्रेन सेटों का ऑर्डर दिया जायेगा

बुलेट ट्रेन
रेल का भविष्य

अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड ट्रेन

- 2023 तक पूर्ण करने का लक्ष्य
- एक मिनट से कम देरी के रिकॉर्ड वाली शिंकानसेन तकनीक - 50 वर्षों में कोई भी हताहत नहीं
- यात्रा समय लगभग 8 घंटे से घटकर 2 घंटे हो जायेगा
- जापान सरकार से बहुत कम ब्याज दर पर कम लागत की फंडिंग, जिससे यह वहन योग्य हो गई है
- प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के बड़े अवसर
- मेक इन इंडिया के जरिए भारत की हाई स्पीड टेक्नोलॉजी में अग्रणी भूमिका होगी

डीजल लोकोमोटिव वर्क्स (डी एल डब्ल्यू) वाराणसी, उत्तर प्रदेश:
मिशन इलेक्ट्रिफिकेशन को संभव बनाने के लिए विश्व में पहली बार डीजल लोको का इलेक्ट्रिक लोको में रूपांतरण

इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फ़ैक्ट्री, मधेपुरा, बिहार:
12,000 एचपी का पहला स्टेट-ऑफ़-द-आर्ट इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव

मेक इन इंडिया

बेहतर सुरक्षा और सुविधाओं से लैस स्मार्ट कोच अब सेवारत

मॉडर्न कोच फैक्ट्री, रायबरेली

- 1,000 कोच प्रति वर्ष के उत्पादन करने हेतु 2010 में कमीशन
- 2014 तक कपूरथला से लाए गए डिब्बों पर मामूली फिनिशिंग का काम
- अगस्त 2014 में पहला पूर्ण कोच निर्मित
- अब - स्वीकृत क्षमता को 1,000 से बढ़ाकर 2,844 कोच / वर्ष किया जाएगा

स्वीकृत

- लातूर, महाराष्ट्र में नया कोच निर्माण कारखाना
- न्यू बोंगाईगाँव, असम में एल एच बी कोचों के नवीनीकरण के लिए वर्कशॉप
- लमडिंग, असम में डेमू / मेनलाइन ई एम यू शेड
- सोनीपत, हरियाणा में रेल कोच नवीनीकरण कारखाना
- झांसी, उत्तर प्रदेश में रेल कोच नवीनीकरण की सुविधाएँ

विद्युतीकृत रेलवे

2021-22 तक भारतीय रेलवे के ब्रॉड गेज रूटों का 100% विद्युतीकरण

लाभ

क्षमता व गति

परिचालन दक्षता में वृद्धि, लाइन क्षमता में वृद्धि और ट्रेनों की औसत गति में सुधार

बचत और ऊर्जा सुरक्षा

ईंधन बिल में प्रति वर्ष लगभग ₹13,500 करोड़ की बचत

सस्टेनेबिलिटी

इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के लिए प्रति टन किमी. पर्यावरण लागत 1.5 पैसे और डीजल ट्रैक्शन के लिए 5.1 पैसे

आधुनिक सिग्नलिंग

- रेलवे में सबसे उन्नत सिग्नलिंग प्रणाली लगाई जाएगी
- 2018-19 में ₹77,912 करोड़ का प्रावधान
- प्रथम चरण में, ई टी सी एस एल 2 की स्थापना के लिए परीक्षण के आधार पर 640 रूट किमी. के 4 खंडों को लिया गया

लाभ

बेहतर सुरक्षा

अधिक क्षमता

समय पालन में सुधार

अधिक गति

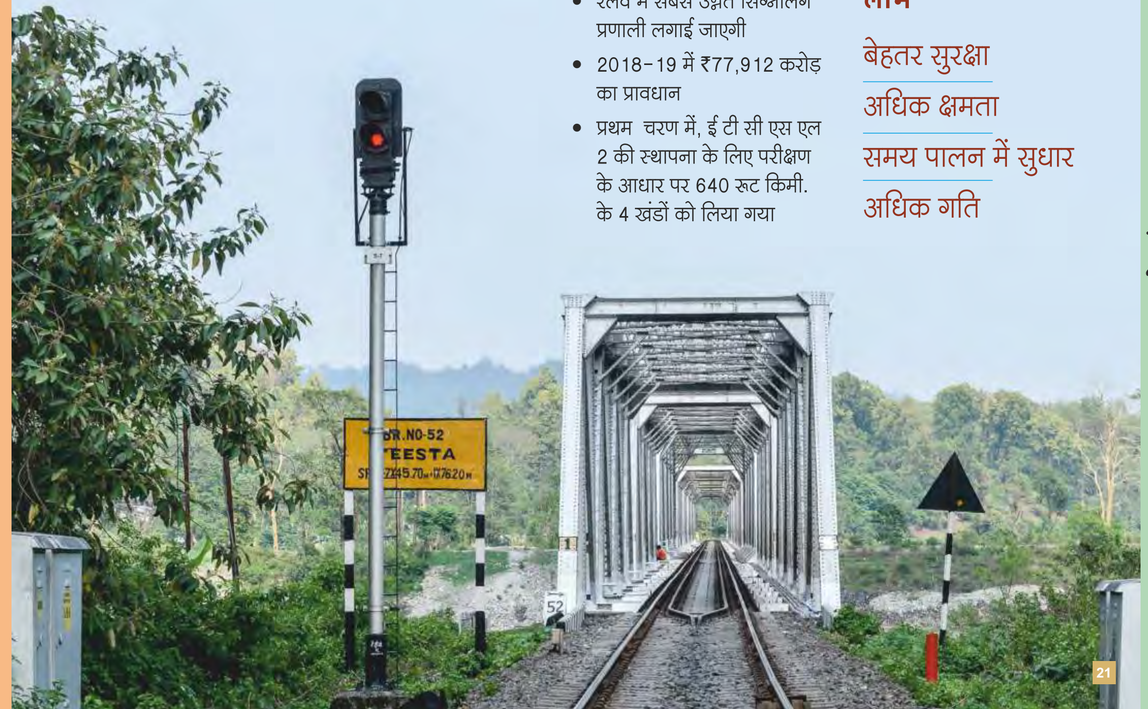

फ्रेट को बढ़ावा

2022 का लक्ष्य: फ्रेट परिवहन के मोडल शेयर में 33% से 45% की वृद्धि

- बुनियादी ढांचे और फ्रेट ट्रैफिक के संचालन में निजी भागीदारी को प्रोत्साहन
  - निजी फ्रेट टर्मिनल (पीएफटी) नीति - 60 पीएफटी अधियूचित
- बजट अनुमान 2019-20 में अपेक्षित ₹1.43 लाख करोड़ की अब तक की सबसे अधिक फ्रेट आय
- अनूठी फ्रेट कॉन्वॉय प्रणाली प्रारंभ
  - कॉन्वॉय के दिनों में फ्रेट थ्रूपुट में 50% तक की वृद्धि
  - 10 जोनल रेलवेज़ पर सफलतापूर्वक संचालित

2013-14 में **1,052 मिलियन टन**

2018-19 में **1,216 मिलियन टन**

अब तक की सर्वाधिक माल ढुलाई

माल ढुलाई में 15.6%की बढ़ोतरी

फ्रेट कॉरीडोर: तरक्की के द्वार

डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डी एफ सी)

- पहले खंड पूर्ण
  - पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भदान से खुर्जा - 200 किमी. पूर्ण
  - पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर रेवाड़ी से मदार - 306 किमी. पूर्ण
- संपूर्ण डीएफसी 2020-21 तक पूर्ण होने की आशा
- माल का तेज़, निर्बाध और आसान प्रवाह सुनिश्चित
- कारखानों और खेतों को बंदरगाहों से जोड़कर आर्थिक विकास और रोजगार सृजन

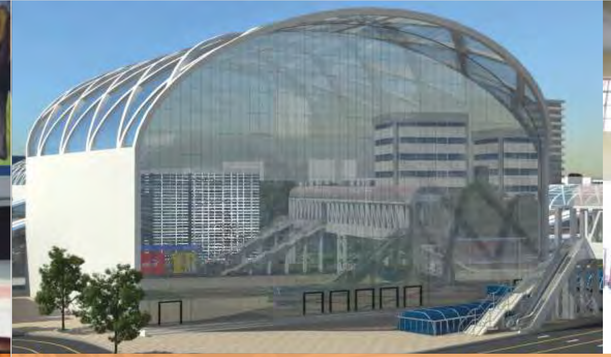

स्टेशनों का विकास

प्रगति के प्लेटफार्म

- विभिन्न व्यावसायिक मॉडलों के माध्यम से पुनर्विकास: 99 साल तक की लम्बी लीज अवधि के साथ वाणिज्यिक और आवासीय विकास
- 4 स्टेशन पर प्रगति- हबीबगंज, गांधीनगर, चारबाग और गोमतीनगर
- स्थानीय कला का उपयोग करके 65 स्टेशनों का सौंदर्यीकरण पूर्ण
- सभी स्टेशन एल ई डी लाइटों से सुसज्जित
- एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं, जैसे वाई-फाई, फूड सेंटर, कियोस्क, रेस्तरां आदि
- लिफ्ट, एस्केलेटर्स, ट्रैवेलेटर्स, रैंप आदि से स्टेशन दिव्यांग अनुकूल

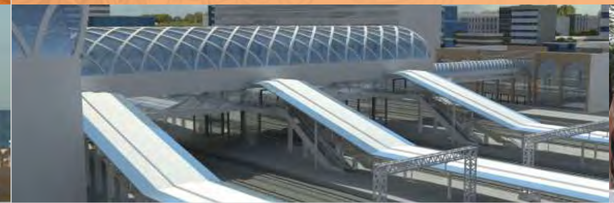

यात्री सेवाओं में बढ़ोत्तरी

लिफ्ट व एस्केलेटर की संख्या में वृद्धि

199
2014

603
अब तक

97
2014

445
अब तक

2014 से अब तक 871 नई ट्रेन सेवाएं प्रारंभ

समय पालन

- डेटा लॉगर्स से प्राप्त ऑटोमैटिक डेटा द्वारा वास्तविक ट्रेन समय का पता चलेगा
- 1,373 ट्रेनों पर देरी की सूचना के लिए एस एम एस सेवाएं

अविस्मरणीय यात्राएं

- यात्रियों के लिए अति आधुनिक सुविधाओं से युक्त तेजस ट्रेनें
- गतिमान ट्रेनें: हाई स्पीड लग्जरी ट्रेन शुरू की गई
- कोचों में अतिरिक्त सुविधाओं वाली हमसफर ट्रेनें शुरू की गईं
- अंत्योदय ट्रेनें: आधुनिक सुविधाओं के साथ लंबी दूरी की पूरी तरह से अनारक्षित ट्रेन

यात्री कोचों का अपग्रेडेशन

- आधुनिक सुविधाओं के साथ दीन दयालु और अनुभूति कोच शुरू किए गए
- पुनर्सज्जित कोचों व सुविधाओं वाली महामना एक्सप्रेस शुरू की गयी
- उदय - 40% अधिक क्षमता वाली उत्कृष्ट डबल-डेकर वातानुकूलित यात्री एक्सप्रेस शुरू की गयी
- ग्लास टॉप विस्टाडोम कोच विशाखापत्तनम-अराकू, मुंबई-गोवा और विश्व धरोहर कालका-शिमला खंड पर शुरू किये गए
- राजधानी / शताब्दी और मेल / एक्सप्रेस ट्रेनों के अपग्रेड के लिए क्रमशः प्रोजेक्ट स्वर्ण और प्रोजेक्ट उत्कृष्ट प्रारम्भ हुए

डिजिटल इंडिया, डिजिटल रेल

- **डिजिटल दुनिया से जुड़ें** - 800 से अधिक स्टेशनों पर हाई स्पीड वाई-फाई सेवा
- **अधिक आसान वेबसाइट-** टिकट कन्फर्म होने की संभावना बताने वाली नई टिकटिंग वेबसाइट (आई आर सी टी सी)
- **लंबी कतारों से राहत-** कागजरहित अनारक्षित टिकटिंग (यू टी एस) की पूरे भारत में शुरुवात
  - 2014-15 के 195 की तुलना में अब प्रति दिन 1,14,000 टिकट बुक
- **स्टेशनों पर आराम -** यात्रियों की सुविधा के लिए रिटायरिंग रूम की ऑनलाइन बुकिंग
- **आसान पारदर्शी टिकटिंग -** हैण्डहेल्ड प्वाइंट ऑफ़ सेल (पी ओ एस) मशीनें
  - सभी ट्रेनों में पी ओ एस मशीनें होंगी
  - खाली सीटों के रियल-टाइम आवंटन द्वारा प्रतीक्षा सूची वाले यात्रियों के लिए सुविधा

गुणवत्तायुक्त खानपान सुविधाएँ

- **16 बेस किचन में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए** स्वच्छता में कमियों का पता लगाने और सुधारने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (ए आई)
- **सुनिश्चित गुणवत्ता:** खानपान सेवाओं का थर्ड पार्टी ऑडिट
- **ओवरचार्जिंग अब नहीं**
  - सभी खाद्य पदार्थों पर एम आर पी का मुद्रण अनिवार्य
  - खाद्य पदार्थों के एम आर पी की जांच के लिए मेनू ऑन रेल्स ऐप लॉन्च किया गया
- **अपना भोजन स्वयं चुनें:** लगभग 325 स्टेशनों पर ई-केटरिंग सेवा: 15,000-16,000 थालियां प्रतिदिन

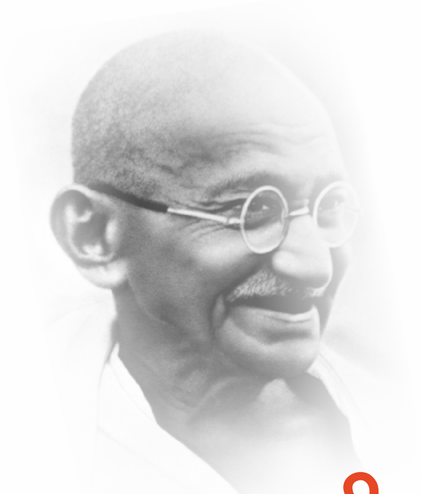

स्वच्छता ही सेवा

"स्वच्छता ईश्वर भक्ति से भी बढ़कर है"
–महात्मा गाँधी

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

स्वच्छ ट्रैक

- 2004-14 (10 वर्ष) के दौरान 9,587 की तुलना में 2014 के बाद (5 वर्ष से कम) 1.8 लाख से अधिक बायो टॉयलेट स्थापित

स्वच्छ स्टेशन

- 697 रेलवे स्टेशनों पर एकीकृत मशीनीकृत सफाई
- 407 प्रमुख स्टेशनों पर स्वच्छता का थर्ड पार्टी सर्वेक्षण

स्वच्छ कोच

- 1,068 ट्रेनों में ऑन बोर्ड हाउसकीपिंग सेवा (ओ बी एच एस)
- 2,167 ट्रेनों में कोच मित्र सेवा शुरू हुई: यात्री एस एम एस या ऐप के माध्यम से कोचों की तत्काल सफाई का अनुरोध कर सकते हैं

स्वच्छ लिनेन

- धुले हुए लिनन की गुणवत्ता में सुधार के लिए मशीनीकृत लॉन्ड्री: मार्च 2014 में 25 से बढ़कर 2018-19 में अब तक 57

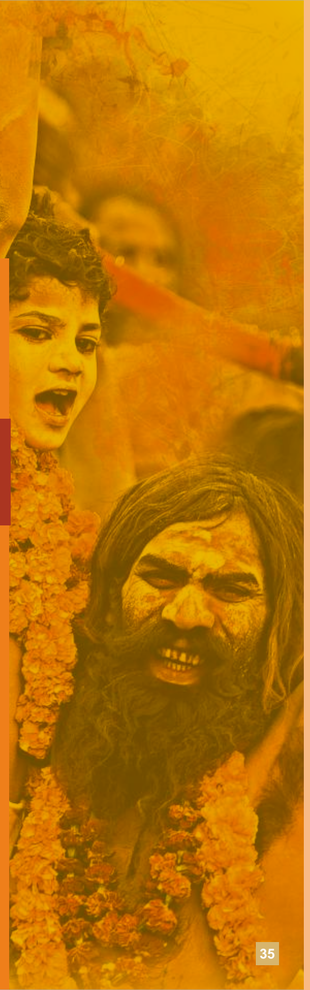

भारत: विश्व की आध्यात्मिक राजधानी

रामायण एक्सप्रेस: भगवान राम की यात्रा का स्मरण

पंज तख्त एक्सप्रेस: सिख धर्म से जुड़े पांच पवित्र तख्तों को जोड़ेगी

बौद्ध सर्किट ट्रेन: भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े क्षेत्रों से होकर गुजरती विश्व स्तरीय सुविधाओं वाली विशेष ट्रेन

धनुषकोडी और पंबन ब्रिज परियोजनाएं: रामेश्वरम और धनुषकोडी (राम सेतु का प्रारंभिक बिंदु) के बीच रेल लाइन, और मुख्यभूमि और पंबन द्वीप को जोड़ते पंबन पुल के निर्माण की योजना

श्री माता वैष्णो देवी तीर्थ जुड़ा: उधमपुर और कटरा के बीच 25 किमी. लाइन से मिलेगी सीधी कनेक्टिविटी और तीर्थयात्रियों को होगा लाभ

माता चिंतपूर्णी तीर्थ जुड़ा: नांगल से तलवाड़ा रेल लाइन के अंदौरा-दौलतपुर चौक खंड को ऊना, हिमाचल प्रदेश में चिंतपूर्णी तीर्थ तक सीधी पहुँच के लिए खोला गया

कुंभ की पुकार

- ₹2,100 करोड़ की परियोजनाएं प्रगति पर अथवा पूर्ण

- 5,100 से अधिक विशेष रूप से प्रशिक्षित रेलवे कर्मचारी, जिनमें 2,600 आर पी एफ कर्मी शामिल हैं, भक्तों की सहायता कर रहे हैं
- कुंभ स्पेशल ट्रेनों में टिकट पर कोई अधिभार नहीं
- 'रेल कुंभ सेवा-2019' ऐप: मेला स्पेशल ट्रेनों, रेलवे स्टेशन के मार्ग, मेला ज़ोन, होटलों, बस अड्डों, आदि के बारे में जानकारी

रेल दृष्टि: भारतीय रेल का एक विहंगम दृश्य

लोग इस माध्यम से जुड़ सकते हैं - raildrishti.cris.org.in

जनता का सूचना द्वारा सशक्तिकरण

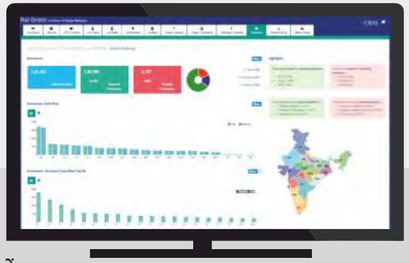

शिकायतें

उपलब्धियां

लाइव ट्रेनें

स्टेशन की तस्वीरें

सेवाएं

श्रमिक कल्याण

विरासत

फ्रेट लोडिंग / अनलोडिंग

पहला रेल विश्वविद्यालय:
परिवहन क्षेत्र के लिए प्रतिभाओं का सृजन

राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान

- शिक्षक दिवस 2018 के दिन वास्तविकता बनी
- दो स्नातक कार्यक्रमों में 103 छात्रों के साथ पहला शैक्षिक सत्र प्रारंभ – परिवहन प्रौद्योगिकी में बी एस सी और परिवहन प्रबंधन में बी बी ए
- अगले 5 वर्षों के लिए ₹421 करोड़ स्वीकृत
- अध्यापक / छात्र विनिमय और संयुक्त अनुसंधान के लिए वैश्विक विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग
- उद्यमिता को बढ़ावा और स्टार्ट अप इंडिया पहल का समर्थन

रेल परिवार का सशक्तिकरण

कार्यबल का सशक्तिकरण

- महाप्रबंधकों को कार्यों को मंजूरी देने की शक्तियां अधिकतम सीमा तक प्रदान की गईं
- त्वरित प्रक्रिया और निर्णय हेतु मंडल रेल प्रबन्धकों को सेवा अनुबंधों की शक्तियां दी गईं

स्वास्थ्य जाँच शिविर

ऐतिहासिक भर्ती अभियान

- 1.5 लाख रिक्तियों पर भर्ती प्रक्रिया जारी
- अगले 2 वर्षों में 2.3 लाख भर्तियाँ

प्रोजेक्ट सक्षम के अंतर्गत प्रशिक्षण

- सभी कर्मचारियों को 5 दिन का कार्य स्थल पर प्रशिक्षण
- 12 लाख से अधिक कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जो एक कीर्तिमान है
- स्किल अपग्रेडेशन और उत्पादकता में वृद्धि

व्यापार करने में आसानी

सेवाओं के लिए सामान्य ठेकों की शर्तें लागू

- सेवा ठेकेदारों के लिए आसान पंजीकरण प्रक्रिया

प्रोक्योरमेंट व्यवस्था में बदलाव

- ई-रिवर्स नीलामी नीति जारी
- एकल वेब-पोर्टल के माध्यम से 100% ई-प्रोक्योरमेंट
- सरकारी ई-मार्केटप्लेस के माध्यम से आम उपयोग की वस्तुओं / सेवाओं की अनिवार्य खरीद

अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन (आर डी एस ओ) में सरल अनुमोदन प्रक्रियाएं

- प्रक्रिया समय 30 महीने से घटाकर 6 महीने कर दिया गया

आई आर ई पी एस पोर्टल पर पंजीकृत विक्रेताओं की कुल संख्या में 5 गुना से अधिक की वृद्धि

2014 में
19,867

जनवरी, 2019 तक
1,07,541

ई-निविदाओं और ई-नीलामी की जानकारी के लिए एंड्रॉइड ऐप IREPS-आपूर्ति लॉन्च किया गया

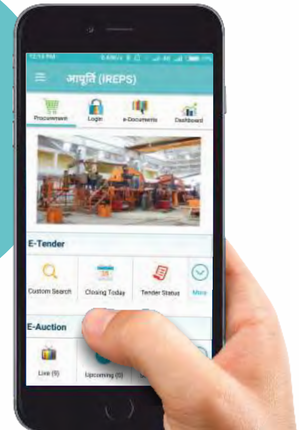

खेलों के क्षेत्र में भारत का गौरव

रेलवे द्वारा शानदार प्रदर्शन

- 4 रेलवे खिलाड़ी 'पद्मश्री' से सम्मानित
- 40 राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पोडियम फिनिश
- राष्ट्रमंडल खेलों में 24 पदक (2014 और 2018) और एशियाई खेलों में 52 पदक (2014 और 2018)

खिलाड़ियों को प्रोत्साहन

- उत्कृष्ट एथलीटों के लिए 330 दिनों का विशेष आकस्मिक अवकाश, नकद पुरस्कार और आउट ऑफ टर्न पदोन्नति
- 7 खिलाड़ी अधिकारी के रूप में पदोन्नत
- कुलदीप सिंह, कुश्ती कोच, अधिकारी के रूप में पदोन्नत

सतीश कुमार शिवलिंगम

मीरा चानू

कोयला क्षेत्र में प्रगति

कोयले की खोज हेतु ड्रिलिंग

6.9 लाख मीटर
2013-14

13.7 लाख मीटर
2017-18

2018-19 में
13.67 लाख मीटर का लक्ष्य

कोल इंडिया का कोयला उत्पादन

- 2014 से अब तक उत्पादन में हुई 105 मिलियन टन की वृद्धि
- 2013-14 के पहले इसे प्राप्त करने में लगभग 7 वर्ष लगे थे

2018-19 के लिए
610 मिलियन टन का लक्ष्य

कोल इंडिया का ऑफ़टेक

471 मिलियन टन
2013-14

580 मिलियन टन
2017-18

2018-19 के लिए
610 मिलियन टन का लक्ष्य

.....परिणामस्वरूप

पर्याप्त कोयला भंडार

- क्रिटिकल स्टॉक वाले कोयला प्लान्टों की संख्या कुल 125 में से केवल 4 (20 फरवरी, 2019 तक) जबकि 2014 में दो तिहाई कोयला प्लान्ट क्रिटिकल स्टॉक वाले थे

कोयले के आयात में कमी

- पहले के ट्रेंड के अनुसार, 2017-18 में आयात 380 मिलियन टन तक पहुंच गया होता
- प्रति वर्ष ~200 मिलियन टन बनाए रखा गया

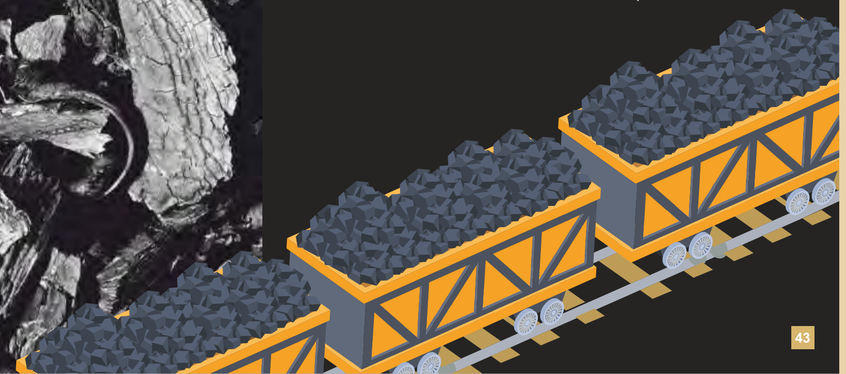

ऊर्जा संयंत्रों को लाभ

कोयले की बेहतर गुणवत्ता

- कोयले की गुणवत्ता को सत्यापित करने के लिए थर्ड पार्टी सैंपलिंग प्रक्रिया
- पॉवर प्लान्टों को 100% क्रश्ड कोयला
- कोल इंडिया और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी की सभी खानों का रिग्रेडेशन

बिजली की लागत में कमी

- बिजली की प्रति यूनिट उत्पन्न करने के लिए आवश्यक कोयले की मात्रा (विशिष्ट कोयला खपत) 2014 के बाद से 8% कम

न्यू इंडिया के लिए कोयला क्षेत्र में सुधार

व्यावसायिक कोयला खनन

- 1973 में राष्ट्रीयकरण के बाद कोयला खनन में सबसे महत्वाकांक्षी सुधार
- आयात पर निर्भरता को कम करेगा और सुनिश्चित कोयला आपूर्ति के माध्यम से ऊर्जा सुरक्षा लाएगा

कोयला ब्लॉकों की पारदर्शी ई-नीलामी और आवंटन

- 2014 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 204 कोयला खानों को रद्द कर दिया गया
- आज
  - 85 कोयला खानों की सफलतापूर्वक नीलामी और आवंटन किया गया
  - कोयला उत्पादक राज्यों को 100% राजस्व

रॉयल्टी का भुगतान (39% वृद्धि)

₹24,922 करोड़
पूर्ववर्ती 4 सालों के दौरान भुगतान किया गया

₹34,709 करोड़
पिछले 4 साल में भुगतान किया गया

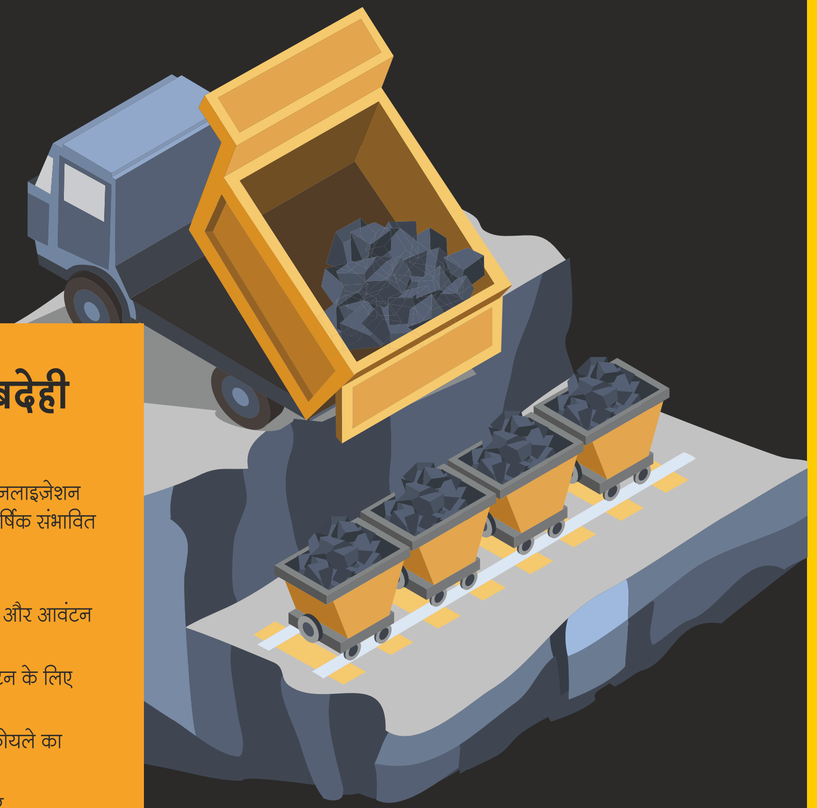

पारदर्शिता एवं जवाबदेही

कोल लिंकेज का रैशनलाइज़ेशन

- अब तक 61 मिलियन टन के कुल रैशनलाइज़ेशन के साथ लगभग ₹3,651 करोड़ की वार्षिक संभावित बचत

शक्ति

(भारत में पारदर्शी रूप से कोयले के दोहन और आवंटन की योजना)

- कोयला लिंकेज की नीलामी और आवंटन के लिए परिवर्तनकारी नीति
- इससे संभव होगी सस्ती बिजली और कोयले का पारदर्शी आवंटन
- 18 ईंधन आपूर्ति समझौतों पर हस्ताक्षर

कोयले की कुल लोडिंग में बढ़ोतरी

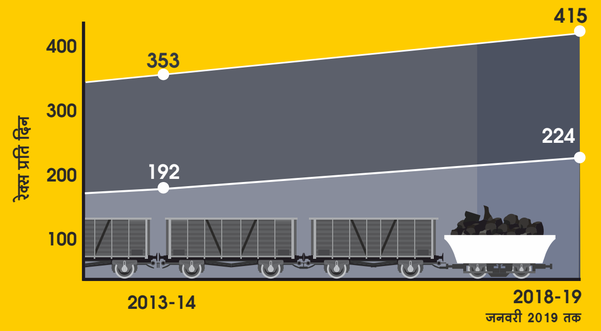

रेल कोयला सहभागिता

कोयला परिवहन को बढ़ाने के लिए कोयला निकासी की 14 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समयसीमा स्थापित

- ओडिशा में झारसुगुड़ा-बारपाली (52 किमी.) रेल लाइन मार्च 2018 में पूरी की गई
- लंबे समय से प्रतीक्षित झारखंड की टोरी-शिवपुर (44 किमी.) रेल लाइन सितंबर 2018 में पूरी की गई